



## **The Madhya Pradesh Cow Slaughter Prohibition Act, 2004**

Act No. 06 of 2004

Amendment appended: 14 of 2024

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

# THE MADHYA.PRADESH GOVANSH VADH PRATISHEDH ADHINIYAM, 2004<sup>1</sup>

[No. 6 of 2004]\*

[Received the assent of the Governor on the 26th March, 2004; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 29th March, 2004.]

<sup>1</sup>[An Act to provide, in the interest of general public and to maintain communal harmony and peace, for prohibition of slaughter of cow progeny, and for preservation and conservation of cow progeny and for matters connected therewith or incidental thereto.]

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title, extent and commencement.**— (1) This Act may be called the **Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004.**

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

**2. Definitions.**— In this Act, unless the context otherwise requires—

- (a) "beef" means flesh of cow progeny, whose slaughter is prohibited under this Act;
- (b) "cow progeny" means cows, bulls, bullocks and calves of cows;
- (c) "Competent Authority" means a person appointed by the State Government by notification to perform in any local area specified therein, the functions of a competent authority under this Act;
- (d) "institution" means any charitable institution registered under any enactment for the time being in force, established for the purpose of keeping, breeding and maintaining cow progeny or for the purpose of reception, protection, care, management and treatment of infirm, aged and diseased cow progeny;
- <sup>2</sup>(e) "slaughter" means killing by any method whatsoever and includes maiming or inflicting of physical injury which in the ordinary course will cause death or doing any act with the intention of causing unnatural death;
- (ea) "transport" means to carry cow progeny from one place to another either by any vehicle or on foot, except when such transport is for *bonafide* agricultural or ancillary purposes;

\* Published in Madhya Pradesh Rajpatra (Asadharan) dated 29-03-2004 at pp. 198-198 (7).

1. Subs. by M.P. Act No. 43 of 2011.  
2. Subs. by M.P. Act No. 43 of 2011.

# मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004

[क्रमांक 6 सन् 2004]\*

[दिनांक 26 मार्च, 2004 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" दिनांक 29 मार्च, 2004 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

[जनसाधारण के हित में और सांप्रदायिक सद्भाव तथा शांति बनाए रखने के लिए गौवंश वध का प्रतिषेध करने तथा गौवंश के परिरक्षण तथा संरक्षण के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।]

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।

(3) यह "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.— इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "गौ-मांस" से अभिप्रेत है गौवंश जिसका वध इस अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है, का मांस;

(ख) "गौवंश" से अभिप्रेत है गाय, सांड, बैल और गाय के बछड़े;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया हो;

(घ) "संस्था" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन गौवंश को रखने, उनके प्रजनन तथा भरण-पोषण करने के प्रयोजन के लिए या अशक्त, बूढ़े और रोगी गौवंश को ग्रहण करने, उनका संरक्षण, देखभाल, प्रबंध तथा उपचार करने, के प्रयोजन के लिए स्थापित की गई रजिस्ट्रीकृत कोई पूर्त संस्था;

(ङ) "वध" से अभिप्रेत है, किसी भी पद्धति से, चाहे वह कुछ भी हो, हत्या करना और उसमें इस प्रकार अंगहीन करना या कोई शारीरिक चोट पहुंचाना भी सम्मिलित है जिससे सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो जाए या अप्राकृतिक मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कृत्य करना;

(ड क) "परिवहन" से अभिप्रेत है, सिवाय उस स्थिति के, जबकि ऐसा परिवहन वास्तविक कृषि या आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो, गौवंश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो किसी यान द्वारा या पैदल ले जाना;

\* मध्यप्रदेश के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29-03-2004 पृष्ठ 198-198(7) पर प्रकाशित।

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 43 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. म.प्र. अधिनियम क्र. 43 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (eb) **“transporter”** means and includes the person,—
- (i) who is the owner of the vehicle carrying the cow progeny or beef, if the cow progeny or beef has been booked under his instruction or within his knowledge;
  - (ii) who for the time being in charge of the vehicle and his assistant, carrying the cow progeny or beef;
  - (iii) who is in charge of transport company, for the time being, transporting the cow progeny and beef, if booking has been undertaken under his instruction or within his knowledge;
  - (iv) who is the partner of a transport firm, if the booking has been undertaken under his instruction or within his knowledge;]
- (f) **“Veterinary Officer”** means a person appointed as a Veterinary Officer under Section 3;
- (g) **“Vehicle”** means any mechanically or manually driven conveyance used on land, water or air.

**3. Appointment of Veterinary Officer.**—The Commissioner-cum-Director of Veterinary Services, Madhya Pradesh, may, by a general or special order, appoint for the purposes of this Act, any person, or class of persons, to be the Veterinary Officer for a local area specified in the order.

**[4. Prohibition of slaughter of cow progeny.**— No person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered for slaughter of any cow progeny by any means.

**5. Prohibition on possession and transport of beef.**— No person shall have in his possession or shall transport beef of any cow progeny slaughtered in contravention of the provisions of this Act.]

**[6. Prohibition on transport of cow progeny for slaughter.**—No person including transporter shall transport or offer for transport or cause to be transported any cow progeny himself or by his agent, servant or by any other person acting in his behalf within the State or outside the State for the purpose of its slaughter in contravention of the provisions of this Act or with the knowledge that it will be or is likely to be so slaughtered.

**6A. Prohibition of export of cow progeny and grant of permit.**— (1) No person including transporter shall export or cause to be exported any cow progeny himself or by his agent, servant or by any other person acting in his behalf from any place of the State to any place out side the State without permit as provided in subsection (2).

(2) The Competent Authority may grant a permit within seven days on presenting application in this behalf, in such manner as may be prescribed for export of cow progeny from Madhya Pradesh for agricultural of dairy farming purposes or

1. Subs. by M.P. Act No. 43 of 2011.

2. Subs. by M.P. Act No. 42 of 2011.

(ड ख) "परिवाहक" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है वह व्यक्ति,—

- (एक) जो गौवंश या गौमांस का परिवहन करने वाले यान का स्वामी है, यदि गौवंश या गौमांस उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी में बुक किया गया है;
- (दो) जो गौवंश या गौमांस का परिवहन करने वाले यान का तत्समय प्रभारी तथा उसका सहायक है;
- (तीन) जो गौवंश तथा गौमांस का परिवहन करने वाली परिवहन कम्पनी का तत्समय प्रभारी है, यदि बुकिंग उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी में की गई है;
- (चार) जो किसी परिवहन फर्म का भागीदार है, यदि बुकिंग उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी में की गई है।]
- (च) "पशु चिकित्सा अधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन पशु चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
- (छ) "यान" से अभिप्रेत है भूमि, जल या वायु मार्ग से उपयोग में लाए गए यांत्रिकी या हस्तचलित वाहन।

3. पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति.— आयुक्त-सह-संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं मध्यप्रदेश सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को आदेश में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

4. गौवंश के वध का प्रतिषेध.— कोई भी व्यक्ति, किन्हीं भी साधनों से, किसी गौवंश का न तो वध करेगा, न वध करवाएगा और न तो उन्हें वध के लिए देगा और न ही उन्हें वध के लिए दिलवाएगा।

5. गौमांस रखने और उसके परिवहन का प्रतिषेध.— कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में वध किए गए किसी गौवंश के गौमांस को अपने कब्जे में नहीं रखेगा या उसका परिवहन नहीं करेगा।]

6. वध के लिए गौवंश के परिवहन पर प्रतिषेध.— कोई भी व्यक्ति जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है, किसी गौवंश का, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में, उसके वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए कि उसका इस प्रकार वध किया जाएगा या उसके वध किए जाने की संभावना है, राज्य के भीतर या राज्य के बाहर, स्वयं या अपने एजेंट, नौकर द्वारा या उसके निमित्त कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, परिवहन नहीं करेगा या उसे परिवहन के लिए नहीं देगा या उसका परिवहन नहीं करवाएगा।

6-क. गौवंश के निर्यात का प्रतिषेध और अनुज्ञापत्र का मंजूर किया जाना.— (1) कोई भी व्यक्ति, जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है, किसी गौवंश का स्वयं या अपने एजेंट, नौकर द्वारा या उसके निमित्त कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उपधारा (2) में यथा उपबंधित अनुज्ञापत्र के बिना राज्य के किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को निर्यात नहीं करेगा या निर्यात नहीं करवाएगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, कृषिक या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए या किसी पशु मेले में भाग लेने के लिए और इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए जो वध के प्रयोजन से भिन्न हों, मध्यप्रदेश से गौवंश का निर्यात करने के लिए इस निमित्त आवेदन प्रस्तुत किए जाने के सात

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 43 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. म.प्र. अधिनियम क्र. 43 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

for participation in a cattle fair and like purposes except for the purpose of slaughter.

(3) Any person seeking permit under sub-section (2) aggrieved by an order of the Competent Authority may make an application within thirty days from the date of receipt of the order to the Divisional Commissioner, and the Divisional Commissioner may upon such application call for the examine the record of the case for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality or propriety of any order and may pass such order as it may deem just and proper and the order passed by the Divisional Commissioner shall be final and shall not be called in question in any civil court.

**6B. Prohibition of transporting cow progeny via Madhya Pradesh and grant of transit permit.**— No person including transporter shall transport cow progeny via Madhya Pradesh State and if any person including transporter wants to transport any cow progeny from one State to other via Madhya Pradesh State, then he shall take transit permit from Competent Authority in such manner as may be prescribed.]

**7. Strengthening of institutions.**— The State Government shall take necessary steps for strengthening of institutions which are engaged in welfare activities of cow progeny.

**8. Levy of charges.**— The person incharge of institution may levy such charges as may be prescribed, for care and maintenance of infirm, aged and diseased cow progeny from their owners.

**9. Penalties.**— (1) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of Section 4 shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than five thousand rupees.

(2) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of Sections 5, 6, 6A and 6B shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years and with fine which shall not be less than five thousand rupees.]

**10. Offences to be cognizable and non-bailable.**— Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) all offences under this Act shall be cognizable and non-bailable.

**11. Power of entry, inspection, search and seizure.**— (1) For the purpose of enforcing the provisions of this Act, the Competent Authority of any person authorized by the Competent Authority in writing in this behalf shall have power to enter and inspect any premises within the local limits of his jurisdiction, where he has reason to believe that an offence under this Act has been, is being or is likely to be committed and shall take necessary action.

(2) Every person in occupation of any such premises as is specified in sub-

---

1. Subs. by M.P. Act No. 43 of 2011.

2. Subs. by M.P. Act No. 43 of 2011.

दिन के भीतर अनुज्ञापत्र मंजूर कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञापत्र की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति, जो सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित है, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर संभागीय आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, और संभागीय आयुक्त ऐसा आवेदन किया जाने पर, किसी आदेश की शुद्धता उसकी वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मामले के अभिलेख मंगा सकेगा और उनका परीक्षण कर सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे और संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

**6-ख. मध्यप्रदेश से होकर गौवंश के परिवहन का प्रतिषेध और अभिवहन अनुज्ञापत्र का दिया जाना.**— कोई भी व्यक्ति, जिसमें परिव्राहक भी सम्मिलित है, मध्यप्रदेश राज्य से होकर गौवंश का परिवहन नहीं करेगा और यदि कोई व्यक्ति, जिसमें परिव्राहक भी सम्मिलित है, एक राज्य से दूसरे राज्य को मध्यप्रदेश राज्य से होकर किसी गौवंश का परिवहन करना चाहता है तो वह सक्षम प्राधिकारी से ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, अभिवहन अनुज्ञापत्र प्राप्त करेगा।]

**7. संस्थाओं का सुदृढीकरण.**— राज्य सरकार ऐसी संस्थाओं के सुदृढीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जो गौवंश कल्याण में लगी हुई हों।

**8. प्रभारों का उद्ग्रहण.**— संस्था का भारसाधक व्यक्ति, अशक्त, बूढ़े और रोगी गौवंश की देखभाल तथा भरण-पोषण के लिए उनके स्वामियों से ऐसे प्रभारों का उद्ग्रहण कर सकेगा जैसा कि विहित किया जाए।

**9. शास्ति.**— (1) जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का प्रयास करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा, किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई धारा 5, 6, 6-क और 6-ख के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का प्रयास करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से जो छह मास से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा।]

**10. अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना.**— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे।

**11. प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण की शक्ति.**— (1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी को या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के किसी भी ऐसे परिसर में, जिसके कि संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, प्रवेश करने तथा उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी और वह आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गए किसी परिसर पर-अधिभोग रखता हो, सक्षम प्राधिकारी को या सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उस परिसर में ऐसा प्रवेश

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 43 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. म.प्र. अधिनियम क्र. 43 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

section (1) shall allow the Competent Authority or any person authorized by the Competent Authority in writing, such access to the premises as he may require for the aforesaid purpose, and shall answer any question put to him by the Competent Authority or the person authorized, as the case may be, to the best of his knowledge and belief.

(3) Any police officer not below the rank of Head constable or any person authorized in this behalf by Competent Authority may, with a view to securing compliance of the provisions of Sections 4, 5, 6A and 6B or for satisfying himself that the provisions of the said sections have been complied with.

- (a) stop, enter and search any vehicle used or intended to be used for the export of cow progeny or beef;
- (b) seize or authorize the seizure of cow progeny, in respect of which he suspects that any provision of Sections 4, 5, 6, 6A and 6B has been, is being or is about to be contravened, along with the vehicle in which such cow progeny or beef are found and thereafter take or authorize the taking of all measures necessary for securing the production of the cow progeny and vehicle so seized, in a court and for their safe custody pending the trial.

(4) The provision of Section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this Section.

(5) In case of any violation of Sections 4, 5, 6, 6A and 6B, the police shall be empowered to seize the vehicle, cow progeny and beef, and the District Magistrate shall confiscate such vehicles, cow progeny and beef in such manner as may be prescribed.

**11A. Appeal against order of confiscation.**— (1) Any person aggrieved by an order of confiscation under sub-section (5) of Section 11 may, within thirty days of the order, or if fact of such order has not been communicated to him, within thirty days of date of knowledge of such order, prefer an appeal in writing with certified copy of order of confiscation, accompanied by such fee and payable in such manner as may be prescribed, to the Divisional Commissioner (hereinafter referred to as the Appellate Authority).

**Explanation.**— The time requisite for obtaining certified copy or order of confiscation shall be excluded while computing period of thirty days referred to in this sub-section.

(2) The Appellate Authority referred to in sub-section (1) shall, on presentation of memorandum of appeal, issue a notice for hearing of appeal to the officer effecting seizure and to any other person who in the opinion of the Appellate Authority, is likely to be adversely affected by the order of confiscation, and call for the record of the case :

Provided that no formal notice of appeal need be issued to the appellant,



करने हेतु अनुज्ञात करेगा, जैसा कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित करे और यथास्थिति, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने सर्वोत्तम ज्ञान और और विश्वास के अनुसार देगा।

(3) हेड कांस्टेबल की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, धारा 4, 5, 6, 6-क और 6-ख के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से कि उक्त धाराओं के उपबंधों का अनुपालन किया गया है,—

- (क) गौवंश या गौमांस के निर्यात के लिए उपयोग में लाए गए अथवा उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित किसी यान को रोक सकेगा, उसमें प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;
- (ख) ऐसे गौवंश का, जिसके संबंध में उसे यह संदेह हो कि धारा 4, 5, 6, 6-क और 6-ख के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, उस यान सहित, जिसमें ऐसा गौवंश या गौमांस पाया जाता है, अभिग्रहण कर सकेगा या उसके अभिग्रहण को प्राधिकृत कर सकेगा और उसके पश्चात् इस प्रकार अभिगृहीत किए गए गौवंश और यान को विचारण के लंबित रहने तक, किसी न्यायालय में पेश करने और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समस्त उपाय कर सकेगा अथवा उपाय किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा।

(4) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 100 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

(5) धारा 4, 5, 6, 6-क और 6-ख के किसी उल्लंघन की दशा में, पुलिस किसी यान, गौवंश और गौमांस को अभिगृहीत करने के लिए सशक्त होगी और जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यानों, गौवंश और गौमांस का ऐसी रीति में अधिहरण करेगा जैसी कि विहित की जाए।

**11-क. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील.—** (1) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, या यदि ऐसे आदेश के तथ्यों की संसूचना उसे नहीं दी गई हो तो ऐसे आदेश की जानकारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, संभागीय आयुक्त (जो इसमें इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है), को लिखित में, अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति सहित जिसके साथ ऐसी फीस दी जाएगी और जो ऐसी रीति में देय होगी, जैसी कि विहित जाए, अपील कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण.—** इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जो अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित रहा हो।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया अपील प्राधिकारी, अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किया जाने पर, अभिग्रहण करने वाले अधिकारी और किसी अन्य व्यक्ति को, जिस पर कि अपील प्राधिकारी की राय में अधिहरण के आदेश के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, अपील की सुनवाई की सूचना देगा और मामले के अभिलेख मंगाएगा :

परन्तु अपील की कोई औपचारिक सूचना अपीलार्थी को, अभिग्रहण करने वाले अधिकारी और किसी

officer effecting seizure and any other person likely to be adversely affected as aforesaid, who may be informed in any other manner of date of hearing of appeal by the Appellate Authority.

(3) The Appellate Authority shall send intimation in writing of lodging of appeal to the District Collector.

(4) The Appellate Authority may pass such orders of "interim" nature for custody or disposal (if necessary) of the subject matter of confiscation as may appear to be just or proper in the circumstances of the case.

(5) The Appellate Authority, having regard to the nature of the case or the complexities involved, may permit parties to the appeal to be represented by their respective legal practitioners.

(6) On the date fixed for hearing of the appeal or on such date to which the hearing may be adjourned, the Appellate Authority shall pursue the record and hear the parties to the appeal if present in person, or through any agent duly authorized in writing or through a legal practitioner, and shall thereafter proceed to pass an order of confirmation, reversal or modification of order of confiscation :

Provided that before passing any final order the Appellate Authority may if it is considered necessary for proper decision of appeal make further enquiry itself or cause it to be made by the District Collector and may also allow parties to file affidavits for asserting or refuting any fact that may arise for consideration and may allow proof of facts by affidavits.

(7) The Appellate Authority may also pass such orders of consequential nature, as it may deem necessary.

(8) Copy of final order or of order of consequential nature shall be sent to District Collector for compliance or for passing any appropriate order in conformity with the order of Appellate Authority.

**11B. Revision before Court of Sessions against order of Appellate Authority.**— Any party to the appeal aggrieved by final order or by order of consequential nature passed by the Appellate Authority, may within thirty days of the order sought to be impugned submit an application for revision to the Court of Sessions within the Sessions division whereof the head quarters of the Appellate Authority are situate.

**Explanation.**—In computing the period of thirty days under this section, the time requisite for obtaining certified copy of order of Appellate Authority shall be excluded.]

**12. Rehabilitation.**— The State Government shall, after coming into force of this Act, make rules for the economic rehabilitation of such person, if any, to be directly affected.

**[12A. Maintenance of seized cow progeny.**—The State Government shall take necessary action for the purpose of feeding and maintenance of seized cow progeny in such manner as may be prescribed.]

1. Ins. by M.P. Act No. 43 of 2011.

अन्य व्यक्ति को जिसका पूर्वोक्तानुसार प्रतिकूलतः प्रभावित होना संभाव्य है, दी जाना आवश्यक नहीं होगी जिसे अपील की सुनवाई की तारीख, अपील प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य रीति में सूचित की जा सकती हो।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील किए जाने की सूचना जिला कलक्टर को लिखित में भेजेगा।

(4) अपील प्राधिकारी, अधिहरण की विषयवस्तु की अभिरक्षा या उसके व्ययन (यदि आवश्यक हो) के लिए "अंतरिम" स्वरूप के ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि उसे उस मामले की परिस्थितियों में न्याय संगत या उचित प्रतीत हों।

(5) अपील प्राधिकारी, मामले की प्रकृति या उसमें अन्तर्ग्रस्त जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए अपील के पक्षकारों को, उनका प्रतिनिधित्व उनके अपने-अपने विधि व्यवसायियों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(6) अपील की सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को, या ऐसी तारीख को, जिसको कि सुनवाई स्थगित की जाए, अपील प्राधिकारी अभिलेख का परिशीलन करेगा और अपील के पक्षकारों की, यदि वे स्वयं उपस्थित हों तो वैयक्तिक रूप से या लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किए गए किसी अधिकर्ता के मार्फत या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत, सुनवाई करेगा और उसके पश्चात् अधिहरण के आदेश की पुष्टि करने, उसे उलटने या उसे उपांतरित करने का आदेश पारित करने के लिए अग्रसर होगा :

परन्तु कोई अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व, यदि अपील के उचित विनिश्चय के लिए यह आवश्यक समझा जाए तो अपील प्राधिकारी अतिरिक्त जांच या तो स्वयं कर सकेगा या जिला कलक्टर से करवा सकेगा और किसी ऐसे तथ्य का, जो विचारार्थ उद्भूत हो, प्रख्यान या खण्डन करने के लिए, पक्षकारों को शपथ-पत्र फाइल करने के लिए भी अनुज्ञा दे सकेगा और तथ्यों के सबूत शपथ-पत्र द्वारा दिए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(7) अपील प्राधिकारी पारिणामिक स्वरूप के ऐसे आदेश भी पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे।

(8) अंतिम आदेश की या पारिणामिकस्वरूप के आदेश की प्रति अनुपालन के लिए या अपील प्राधिकारी के आदेश के अनुरूप कोई अन्य समुचित आदेश पारित करने के लिए, जिला कलक्टर को भेजी जाएगी।

**11-ख. अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण.**— अपील का कोई भी पक्षकार, जो अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए अंतिम आदेश से या पारिणामिकस्वरूप के आदेश से व्यथित हो, उस आदेश के, जिसके कि विरुद्ध आक्षेप किया जाना ईप्सित है, तीस दिन के भीतर, उस सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसके सेशन खण्ड के भीतर अपील प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

**स्पष्टीकरण.**— इस धारा के अधीन तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में, वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जो अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित रहा हो।]

**12. पुनर्वास.**— राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति, यदि कोई हों, जो कि इससे प्रत्यक्षतः प्रभावित हों, के आर्थिक पुनर्वास के लिए नियम बना सकेगी।

**[12-क. अभिगृहीत गौवंश का पोषण.**— राज्य सरकार, अभिगृहीत गौवंश को खिलाने-पिलाने और उनके पोषण के प्रयोजन हेतु ऐसी रीति में आवश्यक कार्यवाई करेगी जैसी कि विहित की जाए।]

**13. Protection of action taken in good faith.**— No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

[13A. **Burden of proof on accused.**— Where any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act, shall be on him, if the prosecution is in a position to produce the *prima facie* evidence against him at the first instance.]

**14. Officers exercising powers under this Act deemed to be public servants.**— All Competent Authorities, Veterinary Officers and other persons exercising powers under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

**15. Act to have overriding effect.**—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

**16. Power to remove difficulty.**— If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State government may make such provisions or give such directions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

**17. Power to make Rules.**—(1) The State Government may, by notification, make Rules for carrying out the provisions of this Act which shall have effect from the date of its publication or from such other date as may be specified in this behalf.

(2) The Rules made under this Act shall, as soon as possible after they are published, be laid on the table of the Legislative Assembly.

**18. Repeal and savings.**— The Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhyadesh, 2004 (No. 1 of 2004) is hereby repealed :

Provided that the repeal shall not effect.—

- (i) the previous operation of any law so repealed or anything done or suffered thereunder; or
- (ii) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or
- (iii) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act had not been passed.

13. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.**— किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएंगी।

[13-क. **सबूत का भार अभियुक्त पर होगा.**— जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां यदि अभियोजन प्रथमतः उसके विरुद्ध प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्थिति में है तो यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई अपराध कारित नहीं किया है।]

14. **इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे.**— समस्त सक्षम प्राधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाते हों, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

15. **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.**— इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

16. **कठिनाई दूर करने की शक्ति.**— इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों।

17. **नियम बनाने की शक्ति.**— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी जो उनके प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से प्रभावी होंगे जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों को उनके प्रकाशित होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

18. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अध्यादेश, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2004) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु यह निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा—

(एक) इस प्रकार निरसित की गई किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन की गई या भुगती गई किसी बात; या

(दो) इस प्रकार निरसित की गई किसी विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई भी शास्ति, जप्ती या दण्ड; या

(तीन) पूर्वोक्त प्रकार की किसी भी शास्ति, जप्ती या दण्ड के संबंध में कोई भी अन्वेषण, विधिक, कार्यवाही या उपचार,

और कोई भी ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और कोई भी ऐसी शास्ति, जप्ती या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ है।

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2024—श्रावण 25, शक 1946

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2024

क्र. 12489-156-इक्कीस-अ (प्रा.)- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 14 अगस्त, 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 98 सन् २०२४

### मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, २०२४

[ दिनांक १४ अगस्त, २०२४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १६ अगस्त, २०२४ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

संक्षिप्त नाम और  
प्रारंभ.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 99 का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४ (क्रमांक ६ सन् २००४) की धारा ९९ में,-

(एक) उपधारा (५) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“परंतु इस धारा के अधीन अधिहरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कलेक्टर द्वारा अभिगृहीत किए गए वाहन, गौवंश और गौ-मांस के अधिहरण के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में, विहित प्ररूप में कोई संसूचना, उस अपराध जिसके मद्दे अभिग्रहण किया गया है, पर विचारण की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को न भेज दी जाए.

(दो) उपधारा (५) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

“(६) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धारा ४, ५, ६, ६-क एवं ६-ख के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के, जिसके मद्दे ऐसा अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय, अभिगृहीत वाहन, गौवंश और गौ-मांस के अधिहरण करने के लिए कार्यवाहियों को प्रारंभ करने के बारे में, उपरोक्त उपधारा (५) के अधीन कलेक्टर की ओर से उसे प्राप्त हुई किसी संसूचना के पश्चात् अभिगृहीत किए गए वाहन, गौवंश और गौ-मांस के व्ययन, अभिरक्षा आदि के बारे में कोई भी आदेश नहीं करेगा.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2024

क्र. 12489-156-इक्कीस-अ (प्रा).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 OF 2024

THE MADHYA PRADESH GOVANSH VADH PRATISHEDH (SANSHODHAN)  
ADHINIYAM, 2024

[ Received the assent of the Governor on the 14<sup>th</sup> August, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 16<sup>th</sup> August, 2024. ]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

2. In Section 11 of the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004 (No. 6 of 2004),-

**Amendment of  
Section 11.**

(i) in sub-section (5), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that no order of confiscation shall be made under this section unless the Collector issues an intimation in the prescribed format regarding the initiation of proceedings for confiscation of the seized conveyance, cow progeny and beef to the court having jurisdiction to try the offence for which such seizure has been made.

(ii) after sub-section (5), the following sub-section shall be added, namely:-

“(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or any other law for the time being in force, the Court having jurisdiction to try offences covered by Section 4, 5, 6, 6-A and 6-B on account of which seizure has been made, shall not make any order about the disposal or custody of the conveyance, cow progeny and beef seized after it is received from the Collector an intimation under sub-section (5) above about the initiation of the proceedings for the confiscation of the seized conveyance, cow progeny and beef.”.